

EXAM GENIUS

Presents

GENIUS CURRENT AFFAIRS

In Bilingual

04 April 2026



Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: As per RBI's directive, Two-Factor Authentication (2FA) for all digital transactions became effective from which date?

प्रश्न: RBI के निर्देश के अनुसार सभी डिजिटल लेनदेन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) किस तिथि से प्रभावी हुआ?

- A) January 1, 2026 / 1 जनवरी 2026
- B) March 31, 2026 / 31 मार्च 2026
- C) April 1, 2026 / 1 अप्रैल 2026
- D) July 1, 2026 / 1 जुलाई 2026
- E) April 1, 2027 / 1 अप्रैल 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Two-Factor Authentication (2FA) for all digital transactions became effective from April 1, 2026.
- सभी डिजिटल लेनदेन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया।
- The directive was issued by the Reserve Bank of India (RBI).
- यह निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किया गया था।
- It applies to all digital transactions, including UPI platforms.
- यह UPI सहित सभी डिजिटल लेनदेन पर लागू है।
- The ecosystem has primarily adopted SMS-based OTP as the second authentication factor.
- इकोसिस्टम ने मुख्य रूप से SMS-आधारित OTP को दूसरे सत्यापन कारक के रूप में अपनाया है।
- Users must now verify transactions through OTP, fingerprint, or facial recognition in addition to UPI PIN.
- अब उपयोगकर्ताओं को UPI PIN के अलावा OTP, फिंगरप्रिंट या फेशियल रिकग्निशन से भी लेनदेन सत्यापित करना होगा।
- Screenshots and screen recording are restricted in banking apps to prevent fraud.
- धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकिंग ऐप्स में स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- The initiative aims to reduce fraud and improve accountability in digital payments.
- इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी को कम करना और जवाबदेही बढ़ाना है।





Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBI Established – 1 April 1935
- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Nationalised – 1 January 1949
- RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Current RBI Governor – Sanjay Malhotra
- वर्तमान RBI गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- Deputy Governors – M. Rajeshwar Rao, T. Rabi Sankar, Swaminathan J., Poonam Gupta
- उप गवर्नर – एम. राजेश्वर राव, टी. रबी शंकर, स्वामीनाथन जे., पूनम गुप्ता

EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to RBI

- The Reserve Bank of India (RBI) has capped banks' net open positions in the rupee at \$100 million at the end of each business day.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों की रुपये में नेट ओपन पोजीशन को प्रति दिन \$100 मिलियन तक सीमित कर दिया है।
- The Reserve Bank of India (RBI) was established on April 1, 1935 under the RBI Act, 1934 based on the recommendations of the Hilton Young Commission.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI Act, 1934 के तहत हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों पर हुई थी।
- The Reserve Bank of India (RBI) has mandated the use of Legal Entity Identifier (LEI) and Unique Transaction Identifier (UTI) for financial market transactions.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय बाजार लेनदेन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (LEI) और यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर (UTI) का उपयोग अनिवार्य किया है।
- The Reserve Bank of India (RBI), in consultation with the Government of India, has set the WMA limit at ₹2,50,000 crore for the first half of FY 2026-27 (April–September 2026).
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत सरकार के साथ परामर्श करके FY 2026-27 की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर 2026) के लिए WMA सीमा ₹2,50,000 करोड़ तय की है।
- Reserve Bank of India (RBI) has released the 'Payments Vision 2028', outlining a 3-year roadmap for strengthening the digital payments ecosystem.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 'पेमेंट्स विजन 2028' जारी किया है, जो डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3-वर्षीय रोडमैप प्रस्तुत करता है।
- The Reserve Bank of India approved the budget for FY 2026–27. It also approved the Medium-Term Strategy Framework "Utkarsh 3.0" for 2026–2029.
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026–27 का बजट मंजूर किया। साथ ही "उत्कर्ष 3.0" मध्यम अवधि रणनीति फ्रेमवर्क (2026–2029) को मंजूरी दी गई।
- The Reserve Bank of India (RBI) has approved the Scheme of Amalgamation of Lalbaug Co-operative Bank Ltd., Vadodara with Akhand Anand Cooperative Bank Ltd, Surat





Ques: India's gross GST collections in March 2026 crossed which milestone, showing an 8.8% growth compared to March 2025?

प्रश्न: मार्च 2026 में भारत का सकल GST संग्रह 8.8% की वृद्धि के साथ किस स्तर को पार कर गया?

- A) ₹1.5 lakh crore / ₹1.5 लाख करोड़
- B) ₹1.75 lakh crore / ₹1.75 लाख करोड़
- C) ₹2 lakh crore / ₹2 लाख करोड़
- D) ₹2.5 lakh crore / ₹2.5 लाख करोड़
- E) ₹3 lakh crore / ₹3 लाख करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India's gross GST collections recorded a growth of 8.8% in March 2026 compared to the same month last year.
- भारत का सकल GST संग्रह मार्च 2026 में पिछले वर्ष के समान महीने की तुलना में 8.8% बढ़ा।
- The collections crossed the ₹2 lakh crore mark, indicating strong economic activity and better compliance.
- संग्रह ₹2 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि और बेहतर अनुपालन को दर्शाता है।
- For the financial year 2025-26, gross GST revenues reached ₹22 lakh crore.
- वित्तीय वर्ष 2025-26 में सकल GST राजस्व ₹22 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
- This marks an increase of 8.3% over ₹20 lakh crore recorded in the previous financial year.
- यह पिछले वित्तीय वर्ष के ₹20 लाख करोड़ की तुलना में 8.3% की वृद्धि दर्शाता है।
- The data was released by the Ministry of Finance.
- यह आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- GST Implemented – 1 July 2017
- GST लागू – 1 जुलाई 2017
- Constitutional Amendment – 101st Constitutional Amendment Act, 2016
- संवैधानिक संशोधन – 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
- GST Council Head – Union Finance Minister





Ques: As per RBI's revised capital market exposure norms, what is the cap on loans for subscribing to shares through IPOs or ESOPs per individual?

प्रश्न: RBI के संशोधित पूंजी बाजार एक्सपोजर नियमों के अनुसार, IPO या ESOP के माध्यम से शेयर सदस्यता के लिए प्रति व्यक्ति ऋण की सीमा क्या है?

- A) ₹10 lakh / ₹10 लाख
- B) ₹20 lakh / ₹20 लाख
- C) ₹25 lakh / ₹25 लाख
- D) ₹50 lakh / ₹50 लाख
- E) ₹1 crore / ₹1 करोड़

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- RBI has capped loans for purchase of shares and other eligible securities at ₹1 crore per borrower across the banking system.
- RBI ने पूरे बैंकिंग सिस्टम में शेयर और अन्य पात्र प्रतिभूतियों की खरीद के लिए ऋण सीमा प्रति उधारकर्ता ₹1 करोड़ तय की है।
- Earlier, this limit was ₹20 lakh, which has now been increased to ₹1 crore.
- पहले यह सीमा ₹20 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।
- However, for IPOs, Follow-on Public Offers (FPOs) and ESOPs, the borrowing limit is restricted to ₹25 lakh per individual.
- हालांकि IPO, FPO और ESOP के लिए उधार लेने की सीमा प्रति व्यक्ति ₹25 लाख निर्धारित की गई है।
- The revised capital market exposure rules have been deferred by 3 months—from April 1 to July 1, 2026.
- संशोधित पूंजी बाजार एक्सपोजर नियमों को 3 महीने के लिए 1 अप्रैल से 1 जुलाई 2026 तक स्थगित किया गया है।
- The deferral was due to operational and interpretational concerns raised by banks and market participants.
- यह स्थगन बैंकों और बाजार प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए परिचालन और व्याख्यात्मक मुद्दों के कारण दिया गया।
- The move aims to prevent excessive leverage, curb speculative borrowing and reduce risks in the banking system.





- इस कदम का उद्देश्य अत्यधिक लीवरेज को रोकना, सट्टा उधारी पर नियंत्रण और बैंकिंग जोखिम को कम करना है।
- RBI also clarified that acquisition finance now includes mergers and amalgamations.
- RBI ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण वित्त में अब विलय और समामेलन भी शामिल होंगे।
- Banks must obtain a corporate guarantee from the acquiring company when financing subsidiaries or SPVs.
- जब बैंकों द्वारा सहायक कंपनियों या SPV को वित्त दिया जाता है, तो अधिग्रहणकर्ता कंपनी से कॉर्पोरेट गारंटी लेना अनिवार्य होगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RBI Established – 1 April 1935
- RBI की स्थापना – 1 अप्रैल 1935
- RBI Nationalised – 1 January 1949
- RBI का राष्ट्रीयकरण – 1 जनवरी 1949
- Headquarters – Mumbai
- मुख्यालय – मुंबई
- Governor – Sanjay Malhotra
- गवर्नर – संजय मल्होत्रा
- IPO Full Form – Initial Public Offering
- IPO का पूर्ण रूप – प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम
- FPO Full Form – Follow-on Public Offer
- FPO का पूर्ण रूप – फॉलो-ऑन सार्वजनिक प्रस्ताव
- ESOP Full Form – Employee Stock Option Plan
- ESOP का पूर्ण रूप – कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
- SPV Full Form – Special Purpose Vehicle
- SPV का पूर्ण रूप – विशेष प्रयोजन वाहन
- Capital Market Regulator – SEBI
- पूंजी बाजार नियामक – सेबी
- SEBI Headquarters – Mumbai
- सेबी मुख्यालय – मुंबई
- SEBI Chairman – Tuhin Kanta Pandey
- सेबी अध्यक्ष – तुहिन कांत पांडेय





Ques: The 'Tea Mark' quality certification scheme has been introduced by which body under the Government of India?

प्रश्न: भारत सरकार के अंतर्गत 'टी मार्क' गुणवत्ता प्रमाणन योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है?

- A) FSSAI / भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
- B) APEDA / कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
- C) Tea Board of India / भारतीय चाय बोर्ड
- D) BIS / भारतीय मानक ब्यूरो
- E) Spices Board of India / भारतीय मसाला बोर्ड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Tea Board of India, under the Ministry of Commerce & Industry, has introduced the 'Tea Mark' quality certification scheme.
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चाय बोर्ड ने 'टी मार्क' गुणवत्ता प्रमाणन योजना शुरू की है।
- The scheme will be rolled out in May 2026.
- यह योजना मई 2026 में लागू की जाएगी।
- 'Tea Mark' signifies that the tea has been tested and verified as per control orders and food safety standards.
- 'टी मार्क' यह दर्शाता है कि चाय को नियंत्रण आदेशों और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार परीक्षण और सत्यापित किया गया है।
- The scheme is voluntary and available to manufacturers registered under the Tea (Marketing) Control Order, 2003.
- यह योजना स्वैच्छिक है और चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के तहत पंजीकृत निर्माताओं के लिए उपलब्ध है।
- It aims to curb adulteration, blending with inferior teas, and misrepresentation of origin.
- इसका उद्देश्य मिलावट, घटिया चाय के मिश्रण और उत्पत्ति की गलत जानकारी पर रोक लगाना है।
- The Tea Board will design, select, register and popularise the 'Tea Mark' logo.
- चाय बोर्ड 'टी मार्क' लोगो को डिज़ाइन, चयन, पंजीकृत और लोकप्रिय बनाएगा।
- The scheme ensures digital traceability and verification of supply chain integrity through empanelled testing laboratories.





- यह योजना पैनलबद्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला की डिजिटल ट्रेसिबिलिटी और सत्यापन सुनिश्चित करेगी।
- Tea Board may also develop an e-commerce platform to promote and facilitate the sale of 'Tea Mark' certified teas.
- चाय बोर्ड 'टी मार्क' प्रमाणित चाय की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी विकसित कर सकता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Tea Board of India Established – 1954
- भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना – 1954
- Headquarters – Kolkata, West Bengal
- मुख्यालय – कोलकाता, पश्चिम बंगाल
- Ministry – Ministry of Commerce & Industry
- मंत्रालय – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- Chairman – P.K. Bezbaruah
- अध्यक्ष – पी.के. बेजबरुआह
- India's Rank in Tea Production – 2nd largest in world (after China)
- चाय उत्पादन में भारत का स्थान – विश्व में दूसरा (चीन के बाद)
- India's Rank in Tea Export – 4th largest exporter
- चाय निर्यात में भारत का स्थान – चौथा
- Major Tea Producing States – Assam, West Bengal (Darjeeling), Tamil Nadu, Kerala
- प्रमुख चाय उत्पादक राज्य – असम, पश्चिम बंगाल (दार्जिलिंग), तमिलनाडु, केरल
- Famous Indian Teas – Darjeeling Tea, Assam Tea, Nilgiri Tea (GI Tagged)
- प्रसिद्ध भारतीय चाय – दार्जिलिंग चाय, असम चाय, नीलगिरी चाय (GI टैग)
- Tea (Marketing) Control Order – 2003
- चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश – 2003





Ques: Who has been named the Men's Player of the Year 2025 by the Asian Squash Federation (ASF)?

प्रश्न: एशियाई स्क्वैश महासंघ (ASF) द्वारा 2025 का पुरुष खिलाड़ी (Men's Player of the Year) किसे नामित किया गया है?

- A) Abhay Singh / अभय सिंह
- B) Saurav Ghosal / सौरव घोषाल
- C) Ramit Tandon / रमित टंडन
- D) Mahesh Manganekar / महेश मंगांवकर
- E) Velavan Senthilkumar / वेलावन सेंथिलकुमार

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- India's Abhay Singh has been named the Men's Player of the Year 2025 by the Asian Squash Federation (ASF).
- भारत के अभय सिंह को एशियाई स्क्वैश महासंघ (ASF) द्वारा 2025 का पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया है।
- Japan's Satomi Watanabe won the ASF Women's Player of the Year award.
- जापान की सतोमी वतनाबे को ASF महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला।
- In the junior category, India's Anahat Singh was awarded the Girls' Player of the Year.
- जूनियर श्रेणी में भारत की अनाहत सिंह को गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया।
- The Indian boys' squash team received the Men's Team Award.
- भारतीय बालक स्क्वैश टीम को पुरुष टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- The team earned this recognition after winning a bronze medal at the 2025 World Junior Team Championships held in Egypt.
- यह सम्मान टीम को मिस्र में आयोजित 2025 विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के बाद मिला।

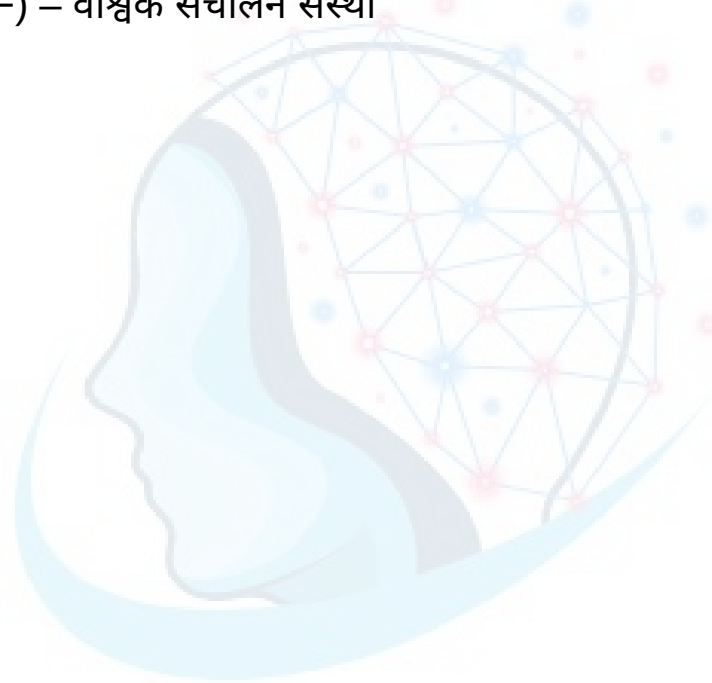
Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Asian Squash Federation (ASF) Founded – 1980





- एशियाई स्क्वैश महासंघ (ASF) की स्थापना – 1980
- Headquarters – Kuala Lumpur, Malaysia
- मुख्यालय – कुआलालंपुर, मलेशिया
- Governing Body in India – Squash Rackets Federation of India (SRFI)
- भारत में संचालन संस्था – स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SRFI)
- World Squash Federation (WSF) – Global governing body
- वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन (WSF) – वैश्विक संचालन संस्था



EXAM
Genius





Recent News Headlines Related to Awards & Winners :

- Lifetime Achievement Award at the International Film Festival of Delhi 2026 : Veteran Telugu actor Nandamuri Balakrishna
- इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली 2026 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड : अनुभवी तेलुगु अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण
- 35th Saraswati Samman (2025) : Ramkumar Mukhopadhyay, an eminent Bengali writer
- 35वें सरस्वती सम्मान (2025) : रामकुमार मुखोपाध्याय
- France's prestigious Legion of Honour (Commandeur rank) : Jawed Ashraf, former Ambassador of India to France and Chairman of the India Trade Promotion Organisation
- फ्रांस का प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर (कमांडर रैंक): जावेद अशरफ, फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष।
- Lifetime Achievement Award at IFFD 2026 : Nandamuri Balakrishna (Padma Bhushan (2025))
- IFFD 2026 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड: नंदमुरी बालकृष्ण (पद्म भूषण (2025))
- "Women Empowerment Trailblazer Award" : Kalpana Soren
- "महिला सशक्तिकरण में अग्रणी पुरस्कार": कल्पना सोरेन
- 2026 Stockholm Water Prize : Kaveh Madani, Director of the United Nations University Institute for Water Environment and Health
- 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार: कावेह मदानी, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक
- KISS Humanitarian Award 2025 : Nita Ambani
- KISS मानवतावादी पुरस्कार 2025: नीता अंबानी
- Mark Lynton History Prize 2026 : Historian William Dalrymple
- मार्क लिंग्टन इतिहास पुरस्कार 2026: इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल





Ques: As per the government's extended import policy, which of the following pulses will continue to attract an import duty of 30%?

प्रश्न: सरकार की विस्तारित आयात नीति के अनुसार, निम्नलिखित में से किस दाल पर 30% आयात शुल्क जारी रहेगा?

- A) Tur / Pigeon Pea (तुर / अरहर)
- B) Urad / Black Matpe (उड़द)
- C) Moong / Green Gram (मूंग)
- D) Yellow Peas (पीली मटर)
- E) Masoor / Red Lentil (मसूर)

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Union government has extended the import policy for key pulses—tur, urad and yellow peas—till March 31, 2027.
- केंद्र सरकार ने प्रमुख दालों—तुर, उड़द और पीली मटर—की आयात नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया है।
- The previous import policy had expired on March 31, 2026.
- पिछली आयात नीति 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी।
- Imports of tur (pigeon pea) and urad (black matpe) will continue to remain duty-free.
- तुर (अरहर) और उड़द का आयात शुल्क-मुक्त बना रहेगा।
- However, yellow peas will continue to attract an import duty of 30%.
- वहीं पीली मटर पर 30% आयात शुल्क जारी रहेगा।
- DGFT issued separate notifications extending the free import policy for tur and urad till March 31, 2027.
- DGFT ने तुर और उड़द की मुक्त आयात नीति को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की अधिसूचनाएं जारी कीं।
- Pulses imports are expected to exceed 5 million tonnes during 2026-27.
- 2026-27 के दौरान दालों का आयात 5 मिलियन टन से अधिक रहने की संभावना है।
- The extension was due to El Niño concerns affecting kharif production and supply disruptions due to West Asia conflict.
- यह विस्तार अल-नीनो के कारण खरीफ उत्पादन पर प्रभाव और पश्चिम एशिया संघर्ष से आपूर्ति बाधित होने के कारण किया गया।





- Yellow peas imports remain free without MIP condition and port restrictions, subject to online import monitoring registration.
- पीली मटर का आयात MIP और बंदरगाह प्रतिबंध के बिना मुक्त है, जो ऑनलाइन आयात निगरानी पंजीकरण के अधीन है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- DGFT Full Form – Directorate General of Foreign Trade
- DGFT का पूर्ण रूप – विदेश व्यापार महानिदेशालय
- Under Ministry – Ministry of Commerce & Industry
- मंत्रालय – वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- MIP Full Form – Minimum Import Price
- MIP का पूर्ण रूप – न्यूनतम आयात मूल्य
- Tur (Pigeon Pea) – अरहर / तुअर दाल
- तुर – अरहर / तुअर दाल
- Urad (Black Matpe) – उड़द दाल
- उड़द – उड़द दाल
- Kharif Pulses – Tur, Urad, Moong
- खरीफ दालें – तुर, उड़द, मूंग
- Sowing Season – June–July | Harvest – October–November
- बुवाई – जून–जुलाई | कटाई – अक्टूबर–नवंबर
- India Pulses and Grains Association Chairman – Bimal Kothari
- इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन अध्यक्ष – बिमल कोठारी





Ques: 'Malwan', recently received by the Indian Navy, belongs to which category of naval vessels?

प्रश्न: हाल ही में भारतीय नौसेना को प्राप्त 'Malwan' किस प्रकार के नौसैनिक जहाजों की श्रेणी में आता है?

- A) Aircraft Carrier / विमानवाहक पोत
- B) Destroyer / विध्वंसक
- C) Frigate / फ्रिगेट
- D) Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) / पनडुब्बी रोधी उथले जल पोत
- E) Patrol Vessel / गश्ती पोत

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Indian Navy has received 'Malwan', the second vessel in a series of eight ASW Shallow Water Crafts (ASW SWC).
- भारतीय नौसेना को 'Malwan' प्राप्त हुआ है, जो 8 ASW Shallow Water Crafts (ASW SWC) की श्रृंखला का दूसरा जहाज है।
- The ship has been built by Cochin Shipyard Limited, Kochi.
- इस जहाज का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि द्वारा किया गया है।
- It is part of an 8-ship programme aimed at strengthening coastal defence.
- यह 8 जहाजों के कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा को मजबूत करना है।
- ASW SWC are specially designed naval vessels used to detect and destroy enemy submarines in shallow coastal waters.
- ASW SWC विशेष रूप से ऐसे नौसैनिक पोत हैं जो उथले तटीय जल में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं।
- These ships enhance India's anti-submarine warfare capabilities in coastal regions.
- ये जहाज तटीय क्षेत्रों में भारत की पनडुब्बी रोधी क्षमता को मजबूत करते हैं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Indian Navy Founded – 26 January 1950
- भारतीय नौसेना की स्थापना – 26 जनवरी 1950
- Headquarters – New Delhi





- मुख्यालय – नई दिल्ली
- Chief of Naval Staff – Admiral Dinesh K Tripathi
- नौसेना प्रमुख – एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी
- Cochin Shipyard Limited – Established in 1972
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड – स्थापना 1972
- Location – Kochi, Kerala
- स्थान – कोच्चि, केरल



EXAM
Genius





Ques: Meghalaya government has partnered with which company to pilot satellite-based internet services in remote hill regions?

प्रश्न: मेघालय सरकार ने दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?

- A) Starlink India / स्टारलिक इंडिया
- B) OneWeb / वनवेब
- C) Jio Satellite / जियो सैटेलाइट
- D) Amazon Kuiper / अमेज़न क्यूपर
- E) BSNL Satellite / बीएसएनएल सैटेलाइट

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Government of Meghalaya has partnered with Starlink India to pilot satellite-based internet services in remote hill regions.
- मेघालय सरकार ने दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिक इंडिया के साथ साझेदारी की है।
- The initiative aims to address connectivity challenges in difficult terrains.
- इस पहल का उद्देश्य कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करना है।
- It will provide high-speed internet access to underserved and remote areas.
- यह दूरस्थ और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगा।
- Satellite-based internet helps overcome infrastructure limitations like lack of fiber networks.
- सैटेलाइट आधारित इंटरनेट फाइबर नेटवर्क की कमी जैसी अवसंरचनात्मक सीमाओं को दूर करने में मदद करता है।
- This move is expected to boost digital inclusion and connectivity in hilly regions.
- यह कदम पहाड़ी क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- State – Meghalaya
- Capital – Shillong
- Chief Minister – Conrad K. Sangma
- Governor – Chandrashekhar H. Vijayashankar





Recent News Headlines Related to MoU and agreement:

- The National Council for Cement and Building Materials (NCB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with UltraTech Cement Limited.
- नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स (NCB) ने अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के साथ समझौता (MoU) किया।
- The Delhi Tourism and Transportation Development Corporation (DTTC) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Prasar Bharati.
- दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTC) ने प्रसार भारती के साथ समझौता (MoU) किया।
- The Government of India signed a working arrangement with the European Union to strengthen aviation manufacturing and safety standards.
- भारत सरकार ने विमानन निर्माण और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ के साथ कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए।
- National Commission for Women partnered with Truecaller to launch a digital safety initiative for women.
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा के लिए Truecaller के साथ साझेदारी की।
- Digital India BHASHINI Division and Pension Fund Regulatory and Development Authority signed an MoU under the “BHASHINI for Seva-Sanchalan” initiative.
- डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने “BHASHINI for Seva-Sanchalan” पहल के तहत समझौता किया।
- The Indian Army signed an MoU with the Ladakh Forest Department. The agreement was signed on World Wildlife Day (3 March 2026). Its objective is to protect iconic species like the Snow Leopard and other Himalayan wildlife, promoting sustainable development in border regions.
- भारतीय सेना ने लद्दाख वन विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता विश्व वन्यजीव दिवस (3 मार्च 2026) को किया गया। इसका उद्देश्य हिम तेंदुए और अन्य हिमालयी वन्यजीवों जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियों की रक्षा करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देना है।





Ques: The RoDTEP scheme, extended till September 30, 2026, provides refunds to exporters in which form?

प्रश्न: 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई गई RoDTEP योजना के तहत निर्यातकों को रिफंड किस रूप में प्रदान किया जाता है?

- A) Direct Bank Transfer / सीधे बैंक ट्रांसफर
- B) Cash Voucher / कैश वाउचर
- C) Transferable Duty Credit Scrip / हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप
- D) Gold Bond / गोल्ड बॉन्ड
- E) Tax Exemption Certificate / कर छूट प्रमाणपत्र

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The government has extended the RoDTEP scheme for six months till September 30, 2026.
- सरकार ने RoDTEP योजना को छह महीने के लिए 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।
- The scheme had earlier expired on March 31, 2026.
- यह योजना पहले 31 मार्च 2026 को समाप्त हो गई थी।
- The extension aims to support exporters facing high freight costs and war-related trade risks in the Gulf and West Asia maritime corridor.
- यह विस्तार खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री गलियारे में बढ़ी माल ढुलाई लागत और युद्ध संबंधी व्यापार जोखिमों से जूझ रहे निर्यातकों की सहायता के लिए किया गया है।
- RoDTEP reimburses taxes, duties and levies at central, state and local levels that are not refunded under any other mechanism.
- RoDTEP केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर उन करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करता है जो किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किए जाते।
- Refunds range from 0.3% to 3.9% of the export value.
- रिफंड निर्यात मूल्य का 0.3% से 3.9% तक होता है।
- These refunds are provided as transferable duty credit scrips.
- ये रिफंड हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के रूप में दिए जाते हैं।
- The scheme covers 10,780 products from DTA units, EoU, AA holders and SEZ units.





- यह योजना DTA, EoU, AA धारकों और SEZ इकाइयों के 10,780 उत्पादों को कवर करती है।
- For FY 2026-27, the allocation for RoDTEP is ₹15,728 crore, including ₹5,346 crore for clearing past dues.
- FY 2026-27 के लिए RoDTEP का आवंटन ₹15,728 करोड़ है, जिसमें ₹5,346 करोड़ पुराने बकाया चुकाने के लिए है।
- Apparel, garments and made-ups are not covered under RoDTEP; they are covered under the RoSCTL scheme.
- परिधान, गारमेंट्स और मेड-अप्स RoDTEP के तहत शामिल नहीं हैं; वे RoSCTL योजना के अंतर्गत आते हैं।
- RoDTEP replaced the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), which was challenged by the USA at WTO.
- RoDTEP ने MEIS योजना की जगह ली, जिसे अमेरिका ने WTO में चुनौती दी थी।
- From April 1, 2021 to December 31, 2025, benefits worth ₹77,262.60 crore have been provided under the scheme.
- 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना के तहत ₹77,262.60 करोड़ के लाभ दिए गए हैं।
- RoDTEP replaced MEIS, which was successfully challenged at the WTO by the United States as it violated global trade norms.
- RoDTEP ने MEIS की जगह ली, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने WTO में वैश्विक व्यापार मानदंडों के उल्लंघन के आधार पर सफलतापूर्वक चुनौती दी थी।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- RoDTEP Full Form – Remission of Duties and Taxes on Exported Products
- RoDTEP का पूर्ण रूप – निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट
- Launched – January 1, 2021
- शुरू – 1 जनवरी 2021
- Replaced – MEIS (Merchandise Exports from India Scheme)
- प्रतिस्थापित – MEIS (मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम)
- Administered by – Ministry of Commerce & Industry
- संचालन – वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- Refund Form – Transferable Duty Credit Scrip
- रिफंड का रूप – हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप
- RoSCTL Full Form – Rebate of State and Central Taxes and Levies
- RoSCTL का पूर्ण रूप – राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों पर छूट





Recent News Headlines Related to Schemes

- PM SVANidhi Scheme was launched in June 2020 to provide collateral-free working capital loans to street vendors.
- पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
- The Centre plans to add battery energy storage in the revamped PM-KUSUM 2.0 scheme.
- केंद्र सरकार PM-कुसुम 2.0 योजना में बैटरी ऊर्जा भंडारण जोड़ने की योजना बना रही है।
- The Ministry of Heavy Industries has extended the PM E-DRIVE scheme till March 31, 2028 to promote electric mobility in India.
- भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए PM E-DRIVE योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है।
- The Union Cabinet approved the modified UDAN scheme with an outlay of ₹28,850 crore for 10 years (2026–36).
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित UDAN योजना को ₹28,850 करोड़ (2026–36) के लिए मंजूरी दी।
- The Immigration Visa Foreigners Registration and Tracking Scheme has been extended for 5 years by the Union Cabinet of India.
- इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।
- Directorate General of Foreign Trade under the Ministry of Commerce and Industry launched the RELIEF (Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation) scheme.
- विदेश व्यापार महानिदेशालय ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत RELIEF योजना शुरू की।
- K Ram Mohan Naidu announced the development of Arasavalli Sri Surya Narayana Swamy Temple under the PRASAD Scheme. The temple is located in Srikakulam, Andhra Pradesh. A foundation stone was laid for modernization of the Indrapushkarini temple tank with ₹24 crore sanctioned





Ques: Under the 4th tranche of the Electronics Components Manufacturing Scheme (ECMS), how many proposals were approved by MeitY?

प्रश्न: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैनुफैक्चरिंग स्कीम (ECMS) की चौथी किश्त के तहत MeitY द्वारा कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई?

- A) 25
- B) 29
- C) 46
- D) 75
- E) 84

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) approved 29 proposals under the 4th tranche of ECMS.
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ECMS की चौथी किश्त के तहत 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
- These proposals involve a projected investment of ₹7,104 crore and expected production of ₹84,515 crore.
- इन प्रस्तावों में ₹7,104 करोड़ का अनुमानित निवेश और ₹84,515 करोड़ का उत्पादन शामिल है।
- The initiative is expected to generate around 14,246 direct employment opportunities.
- इस पहल से लगभग 14,246 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- Earlier, 46 applications worth ₹54,567 crore were approved.
- इससे पहले ₹54,567 करोड़ के 46 आवेदन मंजूर किए गए थे।
- In total, 75 applications have now been approved under ECMS with expected investments of ₹61,671 crore.
- अब तक ECMS के तहत कुल 75 आवेदन मंजूर हो चुके हैं, जिनमें ₹61,671 करोड़ का निवेश अपेक्षित है।
- This exceeds the scheme's investment target of ₹59,350 crore.
- यह योजना के ₹59,350 करोड़ के निवेश लक्ष्य से अधिक है।
- The government increased the ECMS budget allocation to ₹40,000 crore from ₹22,919 crore in the latest budget.

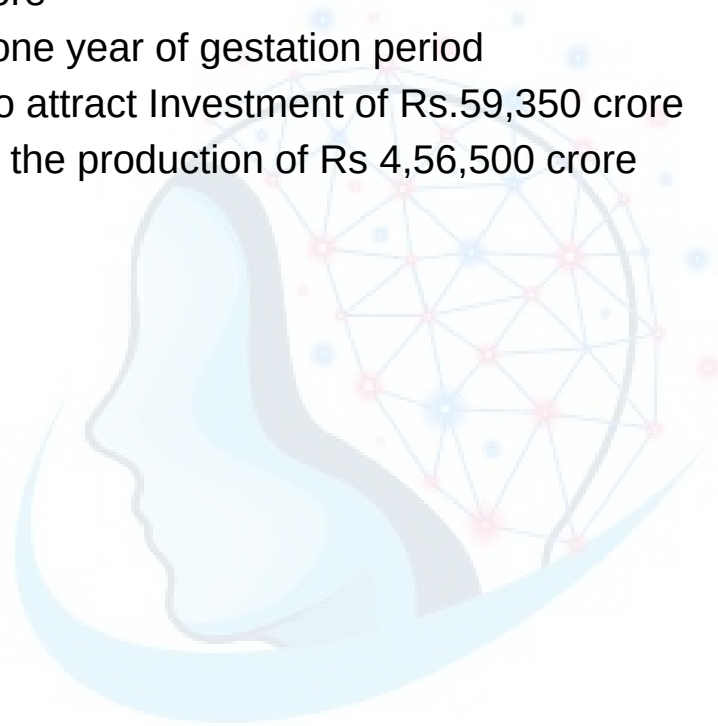




- नवीनतम बजट में सरकार ने ECMS का आवंटन ₹22,919 करोड़ से बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ कर दिया है।

About Electronics Component Manufacturing Scheme (ECMS) Scheme:

- Outlay : Rs 22,919 crore
- Tenure : 6 year, with one year of gestation period
- Investment Target : To attract Investment of Rs.59,350 crore
- Result : It will result in the production of Rs 4,56,500 crore



EXAM
Genius





Ques: The Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026 recognises which city as the sole capital of Andhra Pradesh?

प्रश्न: आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है?

- A) Visakhapatnam / विशाखापत्तनम
- B) Kurnool / कर्नूल
- C) Tirupati / तिरुपति
- D) Vijayawada / विजयवाड़ा
- E) Amaravati / अमरावती

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Lok Sabha has unanimously passed the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2026.
- लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है।
- The Bill recognises Amaravati as the sole capital of Andhra Pradesh.
- इस विधेयक में अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है।
- The provision has been given retrospective effect from June 2, 2024.
- इस प्रावधान को 2 जून 2024 से पूर्व प्रभाव (retrospective effect) दिया गया है।
- The Bill will now be sent to the Rajya Sabha for approval.
- अब यह विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- State – Andhra Pradesh
- राज्य – आंध्र प्रदेश
- Capital – Amaravati
- राजधानी – अमरावती
- Formation Day – 1 November 1956
- स्थापना दिवस – 1 नवंबर 1956





Ques: The Artemis II mission launched by NASA aims to achieve which of the following objectives?

प्रश्न: NASA द्वारा लॉन्च किया गया आर्टेमिस II मिशन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है?

- A) Establish a permanent Moon base / चंद्रमा पर स्थायी आधार स्थापित करना
- B) Conduct a crewed Moon landing / मानव सहित चंद्रमा पर उतरना
- C) Test spacecraft systems and safety for future missions / भविष्य के मिशनों के लिए यान की सुरक्षा और प्रणालियों का परीक्षण करना
- D) Launch a Mars exploration mission / मंगल ग्रह मिशन लॉन्च करना
- E) Deploy satellites in lunar orbit / चंद्र कक्षा में उपग्रह स्थापित करना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- NASA successfully launched the Artemis II mission, marking the first crewed lunar flyby in over 50 years since the Apollo era.
- NASA ने आर्टेमिस II मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो अपोलो युग के बाद 50 वर्षों में पहला मानवयुक्त चंद्र फ्लाईबाई है।
- The mission was launched using the Space Launch System (SLS) rocket from Kennedy Space Center.
- यह मिशन केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया।
- The crew includes four astronauts: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen.
- इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं: रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमी हैंसन।
- The mission duration is about 10 days, during which the Orion spacecraft will travel around the Moon and return to Earth without landing.
- यह मिशन लगभग 10 दिनों का है, जिसमें ओरियन अंतरिक्ष यान चंद्रमा की परिक्रमा कर बिना उतरे पृथ्वी पर वापस आएगा।
- The journey will end with a splashdown in the Pacific Ocean.
- यह यात्रा प्रशांत महासागर में स्प्लैशडाउन के साथ समाप्त होगी।
- The primary objective is to test the safety, reliability, and performance of spacecraft systems and prepare for future human Moon landings.





- इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यान की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रदर्शन का परीक्षण करना तथा भविष्य में मानव चंद्र लैंडिंग की तैयारी करना है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Space Agency – National Aeronautics and Space Administration (NASA)
- अंतरिक्ष एजेंसी – नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)
- Established – 1958
- स्थापना – 1958
- Headquarters – Washington, D.C., USA
- मुख्यालय – वाशिंगटन डी.सी., USA
- Artemis Program – NASA's program to return humans to the Moon
- आर्टेमिस कार्यक्रम – चंद्रमा पर मानवों को वापस भेजने का NASA का कार्यक्रम
- Apollo Missions – First human Moon landing in 1969 (Apollo 11)
- अपोलो मिशन – 1969 में पहली मानव चंद्र लैंडिंग (अपोलो 11)

EXAM
Genius





Ques: NMDC became the first company in India's mining history to surpass which annual iron ore production milestone in FY26?

प्रश्न: NMDC FY26 में भारत के खनन इतिहास में किस वार्षिक लौह अयस्क उत्पादन मील के पत्थर को पार करने वाली पहली कंपनी बनी?

- A) 30 mt annual production mark / 30 मिलियन टन
- B) 40 mt annual production mark / 40 मिलियन टन
- C) 45 mt annual production mark / 45 मिलियन टन
- D) 50 mt annual production mark / 50 मिलियन टन
- E) 60 mt annual production mark / 60 मिलियन टन

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- NMDC achieved a record production of 53 million tonnes (mt) of iron ore in FY26.
- NMDC ने FY26 में 53 मिलियन टन लौह अयस्क का रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया।
- With this, NMDC became the first company in India's mining history to cross the 50 mt annual production mark.
- इसके साथ NMDC भारत के खनन इतिहास में 50 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी बन गई।
- In March 2026 alone, NMDC produced 5.35 mt of iron ore, showing a growth of 51% over last year.
- केवल मार्च 2026 में NMDC ने 5.35 मिलियन टन उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 51% अधिक है।
- Iron ore sales in March stood at 5.90 mt, reflecting a 40% increase year-on-year.
- मार्च में लौह अयस्क की बिक्री 5.90 मिलियन टन रही, जो वर्ष-दर-वर्ष 40% की वृद्धि दर्शाती है।
- The strong performance highlights NMDC's key role in India's mining and steel sector.
- यह प्रदर्शन भारत के खनन और इस्पात क्षेत्र में NMDC की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- NMDC Full Form – National Mineral Development Corporation





- NMDC का पूर्ण रूप – नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
- Founded – 1958
- स्थापना – 1958
- Headquarters – Hyderabad, Telangana
- मुख्यालय – हैदराबाद, तेलंगाना
- Type – Navratna PSU
- प्रकार – नवरत्न PSU
- Ministry – Ministry of Steel
- मंत्रालय – इस्पात मंत्रालय



EXAM
Genius





Ques: Uchral Nyam-Osor, recently in news, has been elected as the Prime Minister of which country?

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहे उच्राल न्याम-ओसोर किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं?

- A) Kazakhstan / कजाकिस्तान
- B) Mongolia / मंगोलिया
- C) Uzbekistan / उज़्बेकिस्तान
- D) Kyrgyzstan / किर्गिस्तान
- E) Turkmenistan / तुर्कमेनिस्तान

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Uchral Nyam-Osor has been elected as the Prime Minister of Mongolia.
- उच्राल न्याम-ओसोर मंगोलिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
- He became the country's third Prime Minister in just nine months.
- वे केवल नौ महीनों में देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं।
- The outgoing Prime Minister Zandanshatar Gombojav resigned amid pressure over corruption allegations.
- निवर्तमान प्रधानमंत्री ज़ंदनशातर गोम्बोजाव ने भ्रष्टाचार के आरोपों के दबाव में इस्तीफा दिया।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Country – Mongolia
- देश – मंगोलिया
- Capital – Ulaanbaatar
- राजधानी – उलानबटार
- Currency – Tögrög
- मुद्रा – टुग्रिक





Newly Appointed Prime Minister & President :

- youngest Prime Minister of Nepal : Balendra Shah (Balen)
- नेपाल के सबसे युवा प्रधान मंत्री: बालेंद्र शाह (बालेन)
- Prime Minister of Nepal : Balendra Shah, popularly known as “Balen”
- नेपाल के प्रधानमंत्री: बलेंद्र शाह, जिन्हें लोकप्रिय रूप से “बालेन” के नाम से जाना जाता है।
- Supreme Leader of Iran : Mojtaba Hosseini Khamenei
- ईरान के सर्वोच्च नेता: मोजतबा हुसैनी खामेनेई
- President of Peru : Jose Maria Balcazar
- पेरू के राष्ट्रपति: जोस मारिया बाल्काज़र
- Prime Minister of the Netherlands : Rob Arnoldus Adrianus Jetten
- नीदरलैंड के प्रधानमंत्री: रॉब अर्नोल्डस एड्रियनस जेटेन
- 8th Prime Minister of Barbados : Mia Mottley
- बारबाडोस की 8वीं प्रधानमंत्री: मिया मोटली
- Prime Minister of Thailand : Anutin Charnvirakul
- थाईलैंड के प्रधानमंत्री: अनुतिन चर्नविराकुल
- Prime Minister of Bangladesh : Tarique Rahman, chairman of the Bangladesh Nationalist Party (BNP)
- बांग्लादेश के प्रधानमंत्री: तारिक रहमान, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष
- Prime Minister of Yemen : Yemen's Foreign Minister Shaya Mohsen Zindani (replaced Salem bin Breik)
- यमन के प्रधानमंत्री: यमन के विदेश मंत्री शया मोहसेन ज़िंदानी (सलेम बिन ब्रेक के स्थान पर)
- President of Uganda : Yoweri Museveni
- युगांडा के राष्ट्रपति: योवेरी मुसेवेनी
- Interim President of Venezuela : Delcy Rodríguez





- Broadcast/Digital (Regional Languages) : Fousiya Musthafa News - Malayalam 24*7
- Environment, Science & Technology Reporting : Jayashree Nandi & Tannu Jain - Hindustan Times
- Environment, Science & Technology Reporting (Broadcast/Digital) : Rohini Krishnamurthy & Dhruval Parekh - Down to Earth
- Uncovering India Invisible : Vijay Pal Dudi - Dainik Bhaskar
- Uncovering India Invisible (Broadcast/Digital) : Basant Kumar - NewsLaundry
- Business & Economic Journalism : Praveen Paramasivam, Munsif Vengattil & Aditya Kalra - Thomson Reuters
- Reporting on Politics and Government : Deeptiman Tiwary - The Indian Express
- Reporting on Politics and Government (Broadcast/Digital) : Rishika Kashyap - Deccan Herald
- Sports Journalism : Srikanth Dhasarathy - DT Next
- Investigative Reporting (Print/Digital) : Mridulika Jha - Aaj Tak
- Investigative Reporting (Broadcast) : Sreya Chatterjee - India Today
- Feature Writing : Vidheesha Kuntamalla - The Indian Express
- Civic Journalism : Sandip Dighe - The Times of India
- Civic Journalism : Sreya Chatterjee & Arvind Ojha - India Today
- Photojournalism : Praveen Jain - The Print
- Books (Non-Fiction) : Aparajith Ramnath : Penguin Random House

EXAM
Genius





Ques: World Autism Awareness Day (WAAD) is observed every year on which date?

प्रश्न: विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस (WAAD) हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) April 1 / 1 अप्रैल
- B) April 2 / 2 अप्रैल
- C) April 3 / 3 अप्रैल
- D) April 5 / 5 अप्रैल
- E) April 7 / 7 अप्रैल

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The United Nations General Assembly observes World Autism Awareness Day (WAAD) every year on April 2.
- संयुक्त राष्ट्र महासभा हर वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस (WAAD) मनाती है।
- The day was designated in 2007 to promote awareness about autism.
- इस दिन को 2007 में ऑटिज़्म के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए घोषित किया गया था।
- It also aims to ensure the rights and inclusion of autistic individuals worldwide.
- इसका उद्देश्य दुनिया भर में ऑटिज़्म से प्रभावित लोगों के अधिकारों और समावेशन को सुनिश्चित करना है।
- Theme for 2026 is "Autism and Humanity - Every Life Has Value".
- वर्ष 2026 की थीम है "Autism and Humanity - Every Life Has Value"।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Declared By – United Nations General Assembly (UNGA)
- घोषित द्वारा – संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
- First Observed – 2008
- पहली बार मनाया गया – 2008





Important days :

- 7 March : Jan Aushadhi Diwas
- 8 March : International Women's Day (Theme "Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls.")
- 10 March : CISF Raising Day
- 10 March : 5th International Day of Women Judges (Theme 2026 Women Judges on the Bench and Beyond: Protecting Access to Justice)
- 11 March (second Wednesday of March) : No Smoking Day 2026
- 12 March (second Thursday of March) : World Kidney Day (theme for 2026 was "Kidney Health for All: Caring for People, Protecting the Planet.")
- 14 March : Pi Day & International Day of Mathematics (Theme 2026 Mathematics and Hope)
- 14 March : 29th International Day of Action for Rivers Theme 2026 Protect Rivers, Protect People
- 15 March : International Day to Combat Islamophobia
- 15 March : World Consumer Rights Day (theme focuses on "Safe Products, Confident Consumers.")
- 16 March : National Vaccination Day (commemorates the launch of the Pulse Polio Programme in 1995)
- 18 March : 9th Global Recycling Day 2026 (Theme 2026 Don't Think Waste – Think Opportunity)
- 20 March : International Day of Happiness (theme for 2026 is "Caring and Sharing".) (first observed in 2013)
- 20 March : World Sparrow Day
- 20 March : United Nations French Language Day
- 20 March : World Day of Theatre for Children and Young People 2026 (Started in 2001)
- 21 March : The International Day of Forests (IDF) (theme for 2026 is "Forests and Economies")
- 21 March : International Nowruz Day
- 21 March : World Day for Glaciers
- 21 March : World Down Syndrome Day (theme "Together Against Loneliness")





IMPORTANT ONE - LINER Current Affairs

The Indian Navy has launched Yard 1280 (Shachi), the first of eleven Next Generation Offshore Patrol Vessels (NGOPVs), at Goa Shipyard Limited. The NGOPVS are being constructed indigenously at Goa Shipyard Limited and Garden Reach Shipbuilders & Engineers.

The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) signed a Memorandum of Understanding with Gati Shakti Vishwavidyalaya. The aim of the MoU is to promote skill development in the aviation sector. Launch a 3-year Bachelor of Science (B.Sc.) in Aviation Maintenance Engineering (AME) from August 2026 (2026–27)

Easy Trip Planners Limited announced a strategic collaboration with NSDC, Sanatan AI and Bhagva platform. The programme is titled “1 Panchayat – 1 Pandit – SANATANAI Shop on Wheels by EMT”. It aims to deploy mobile EV-based service units across up to 2 lakh Panchayats over the next five years.

The total value of ₹2000 banknotes in circulation has declined sharply from ₹3.56 lakh crore in May 2023. As of March 31, 2026, it has reduced to ₹5,501 crore. This indicates that 98.45% of the ₹2000 notes have been returned to the banking system.

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) mandated insurers to prepare financial statements as per Ind AS. The implementation will be effective from April 01, 2026. The decision was approved at the 135th Authority meeting held on March 30.





महत्वपूर्ण समाचार (संक्षिप्त समाचार)

भारतीय नौसेना ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में ग्यारह अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोतों (एनजीओपीवी) में से पहले पोत यार्ड 1280 (शाची) का शुभारंभ किया है। एनजीओपीवी का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विमानन क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। अगस्त 2026 (2026-27) से विमानन रखरखाव इंजीनियरिंग (एएमई) में तीन वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस (बीएससी) पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।

ईज़ी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड ने एनएसडीसी, सनातन एआई और भगवा प्लेटफॉर्म के साथ एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का शीर्षक है "1 पंचायत - 1 पंडित - ईएमटी द्वारा सनातन शॉप ऑन व्हील्स"। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 2 लाख पंचायतों तक मोबाइल ईवी-आधारित सेवा इकाइयों को तैनात करना है।

मई 2023 में प्रचलन में मौजूद ₹2000 के नोटों का कुल मूल्य ₹3.56 लाख करोड़ था, जो 31 मार्च 2026 तक घटकर ₹5,501 करोड़ रह गया है। इससे पता चलता है कि ₹2000 के 98.45% नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा कंपनियों को इंड एस के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह निर्णय 30 मार्च को आयोजित प्राधिकरण की 135वीं बैठक में लिया गया।

